International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 07, July 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

# नेपाल में नक्सलवादी गठजोड़ एवं उत्तराखण्ड की सुरक्षा का विश्लेषण

**डॉ० अवतार सिंह**
**सहायक प्राध्यापक, सैन्य विज्ञान विभाग**
**डॉ० शिवानन्द नौटियाल राजकीय महाविद्यालय वेदीखाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड**
Email: avtarnegi5562@gmail.com

**सारांश**

नेपाल की आन्तरिक स्थिति, जो इस समय बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है, के लिए प्रमुख भूमिका का निर्वाहन वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता, माओवादी कार्यवाहियों तथा इसके अतिरिक्त भारत को क्षीण करने में लगी उपद्रवी ताकतें ही प्रमुखतया समझी जा सकती हैं।जहाँ चीन नेपाल की विदेश नीति को समय-समय पर प्रभावित करता आया है, वहीं पाकिस्तान मौका गवाँए बगैर पाँव पसारता रहा है। दोनो देश नेपाल की आवाम को गुमराह एवं दिगभ्रमित करने पर लगे हुये हैं। जहाँ चीन हमेशा नेपाल को अपन पक्ष में रखने की कवायद में जुटा रहता है, वहीं पाकिस्तान नेपाल में आई०एस०आई० के लिए एक सुनियोजित स्थान ढूँढने में लगा हुआ है। दोनो देशों के इरादे बिल्कुल नेक और शराफत से परे है। अतः दोनो देशों पर दृष्टिपात करते हुए मैं यह समझता हूँ कि चीन वह कीड़ा है, जो पौधों को तने से काटकर उसके अस्तित्व को चोट पहुँचाता है, तो वहीं पाकिस्तान पौधे की जड़ को काटकर पौधों को समूल ही नष्ट करने में अपना हित समझता है। उसके लिए उसकी हरियाली, फूल-पत्ते एवं उसकी (पौधे) सभी के लिए उपयोगिता कोई अहमियत नहीं रखती।

## प्रस्तावना

उत्तराखण्ड के मुख्यतः तीन जिले- पिथौरागढ़, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर भारत-नेपाल सीमा से लगे हुये है। उत्तराखण्ड के इन सीमावर्ती जिलों से सटे नेपाली क्षेत्र माओवादियों के गढ़ माने जाते हैं। ये माओवादी भारत-नेपाल के बीच खुली सीम होने का भरपूर फायदा उठाते हैं। भारत और नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 11,751 कि०मी० है जिसमे उत्तराखण्ड-नेपाल सीमा लगभग 275 कि०मी० तक लगे हुई है।' नेपाल सीमा से लगे हुए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती बलरामपुर, सिद्धार्थनगर व महराजगंज जिला, बिहार के पश्चिम चम्पारन, पूर्वी चम्पार सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज जिला, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिर तथा सिक्किम के उत्तर मंगन जिला और पश्चिम खालसिंग जिला एवम् उत्तराखण्ड के उर्पुयक्त तीन जिले नेपाल सीमा पर स्थित हैं। यह खुली सीमा माओवादी घुसपैठ और अवैध हथियारों एंव विस्फोटकों की आमद रफत का केन्द्र बनती जा रही हैं। खुफिया एजेन्सियों के दस्तावेजों द्वारा इसका खुलासा भी किया जा चुका है।[2]

यदि पुराने आँकड़ों पर दृष्टिपात करें तो उत्तराखण्ड में नेपाली घुसपैठ हमेशा से होती आ रही है। वर्ष 1790 से 1791 तक कुमाँऊ पर नेपाल का आधिपत्य रहा है। इसके बाद 1804 से 1815 तक गढ़वाल के देहरादून तक उन्होंने अपना सम्राज्य फैला दिया था, किन्तु उस समय हालात एवं परिस्थितियाँ कुछ और थीं। गढ़वाल एवं कुमाऊ के राजाओं के आपस में लड़ने-भिड़ने के कारण राज्य दो हिस्सों में बंट चुका था। जिस कारण राज्य में बाहरी शक्तियों के कदम पड़ने शुरू हो गये थे। राजाओं की स्थिति ऐसी थी कि वे बाहरी आक्रमणकारियों को खदेड़ने के बजाय एक दूसरे के प्रति खिलाफत में ही उलझे रहते थे। इसलिए इस समय उन्हें आसानी से उत्तराखण्ड में पैर जमाने का मौका मिल गया था। आज परिस्थितियाँ बदल चुकी है, न राजशाही रही और न ही रजवाड़े। अब उत्तराखण्ड एक नया राज्य बन जाने के बाद लोकतांत्रिक तरीके से

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 07, July 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

चुनी हुई सरकारें राज्य में सत्तासीन हैं। इसके बावजूद माओवादियों की उत्तराखण्ड में दस्तक नवोदित राज्य के कतई हित में नहीं है। यदि वर्तमान समय में कुल पूरे राज्य में नेपालियों की घुसपैठ पर नजर डाले तो इस समय राज्य का कोई भी ऐसा कोना नही छूटा है जहां नेपाली श्रमिक न हो। चाहे नीति-माणा से लेकर उत्तरकाशी पता के सीमांत ब्लाक मोरी या भटवाड़ी हो, यां टिहरी जनपद का घुत्तु-भिलंगना सभी जगह दिहाड़ी मजदूरी से लेकर खेती-बाड़ी का काम अधिकांश नेपालियों के हवाले ही है। यह कहना गलत है कि सभी नेपाली मजदूर आपराधिक प्रवृत्ति के है। लेकिन जितने हैं, उनका खुलासा होना भी इतना आसान काम नहीं है।

यहाँ यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि नेपाली मूल के लोगों की संख्या बढ़ने के बाद पहाड़ में आपराधिक घटनाएँ बढ़ी हैं। उनमें चोरी, लूट-पाट आदि की घटनाओं का ग्राफ ज्यादा है । इसके पीछे यहाँ का क्षेत्रफल, पुलिस और राजस्व के बीच तालमेल का अभाव मुख्य कारण है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश दूरस्थ क्षेत्र राजस्व पुलिस के हवाले है। जबकि शहरों के आस-पास के क्षेत्रों की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी रेगुलर पुलिस के जिम्मे है। दिलचस्प पहलू यह है कि श्रमिकों की पृष्ठभूमि की जानकारी न तो रेगुलर पुलिस के पास उपलब्ध है और न ही राजस्व पुलिस ने इन्हें चिन्हित करने का प्रयास किया। हालाँकि इन नेपाली श्रमिकों द्वारा अभी तक इस क्षेत्र में माओवादियों जैसी मारकाट तो नहीं की, किन्तु जिस तरह से तस्करी के सामान के साथ वे बार्डर पर पकड़े जाते हैं, उससे उनकी पृष्ठभूमि की झलक साफ नजर आती है। पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखण्ड में कई नेपाली संगठन अपने पैर पसार चुके है। यह संगठन नेपाल में राजशाही के विरोध में रह रहे नेपालियों को एकत्र कर लोगों को लामबन्द करने में जुटे हैं। पिछले दिनों सीमान्त जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में भी एक संगठन के द्वारा क्षेत्र में रह रहे नेपालियों के हक-हकूक के लिए सम्मेलन कराया गया था। जिसकी अनुमति के लिए स्थानीय प्रशासन से इजाजत माँगी गयी, किन्तु प्रशासन द्वारा मामले की गम्भीरता को देखत हुये उक्त संगठन को यहां सम्मेलन कराने की अनुमति नहीं दी गयी[3]।

उत्तराखण्ड राज्य की करीब तीन जनपदों की सीमायें नेपाल से आवाजाही के लिए खुली हैं, ऐसे में खतरा और बढ़ जात है। चिन्तायें इसलिए भी हैं क्योंकि उत्तराखण्ड में नेपालियों की संख्या लगातार बढ़त जा रही है। खुफिया रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि हर साल रोजगार की तलाश में उत्तराखण्ड आने वाले नेपालियों की भीड़ में माओवादी नेता भी उत्तराखण्ड धमक रहे हैं और यहीं से अपनी गतिविधि चला रहे हैं। उत्तराखण्ड की परेशानी पर बल इसलिए भी पड़ रहा है, क्योंकि नेपाल में उग्र होते जा रहे माओवादी आन्दोलन में ऐसे लोग भी सिरकत कर रहे है जिनके परिवार के लोग उत्तराखण्ड में सालों में जमे हुए हैं। इसलिए अगर नेपाल में माओवाद को कुचलने के लिए सैन्य हस्तक्षेप बढ़ा या भारत भी इसमें शामिल होता है, तो उसकी हिंसक प्रतिक्रिया उत्तराखण्ड में भी मिलेगी। ऐसी भी खबरें हैं कि यहाँ रह रहे नेपालियों को एकजुट करने के लिए नेपाल से अक्सर माओवादी नेता उत्तराखण्ड आते रहते हैं एवं नियमित बैठकें करते हैं ऐसी भी चर्चा है कि नेपाल के माओवादियों को बौद्धिक खुराक उत्तराखण्ड से भी पहुँच रही है। अगर अब माओवादियों का रूख उत्तराखण्ड की तरफ हुआ तो इस नवोदित राज्य के लिए नयी समस्या खड़ी हो सकती है।[4]

एक एजेन्सी के अनुसार इस बात का अंदेशा ज्यादा है कि कुछ वर्ष पूर्व संदिग्ध गतिविधियों को लेकर प्रतिबन्धित किए गये कतिपय संगठन अब नाम बदलकर फिर से क्षेत्र में सक्रिय हो गये हैं। अभी तक नेपाल-कुमाऊँ सीमा से माओवादी घुसपैठ को रोकने की चुनौती से जूझ रही प्रदेश सरकार को निकट भविष्य में

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 07, July 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

इसी तरह की समस्या से गढ़वाल में भी रूबरू होना पड़ेगा। क्योंकि खुफिया एजेन्सियों की आरम्भिक जॉच में इस तरह के संकेत मिले हैं कि गढ़वाल मण्डल की हिमाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा से भी कुछ ऐसे तत्व प्रवेश कर गये हैं। दरअसल इस अंदेशे के मूल में कुछ पुष्ट कारण भी हैं। एक तो यह गढ़वाल हिमाचल की सीमा पर स्थित इलाका भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से माओवादियों को मुफीद बैठता है, दूसरा हिमाचल प्रदेश की तरफ से प्रतिवर्ष काफी अधिक संख्या में नेपाली मजदूर उत्तराखण्ड-हिमाचल सीमा पर स्थित हिमाचल प्रदेश के गॉवों-कस्बों में नौकरी करते हैं। और यह वास्तविकता से परे नही है कि इन मजदूरों की आड़ में माओवादी गढ़वाल मण्डल के जिलों में भी घुसपैठ कर चुके हैं। अलबत्ता अभी शुरूआत वैचारिक क्रान्ति के रूप में की गई है। हाल के समय में गढ़वाल के दो जिलों में इस तरह की गतिविधियों के लगातार संकेत मिल रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व संदिग्ध गतिविधियों के कारण भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित कर दिये गये दो संगठनों पर भारत सरकार ने वर्ष 2002 में ही प्रतिबन्ध लगाया था। लेकिन खुफिया एजन्सियों का मानना है कि संगठन से जुड़े नये लोग, नये संगठन के साये तले फिर सक्रिय हो गये हैं। हालांकि गढ़वाल में इनके किसी तरह की हिंसक गतिविधियों में संलिप्तता होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा संदेह जरूर है कि इस तरह के संगठनों से जुड़े लोग माओवाद को पनपाने के लिए वैचारिक धरातल तैयार करने में अहम भूमिका रनिभा रहे हैं और प्रदेश सरकार के लिए यही सबसे बड़ी चिन्ता का विषय बना हुआ है। क्योंकि अगर इस दफा बाहर से घुसपैठ करने वाले यहाँ माओवाद के लिए अनुकूल माहौल बनाने में कामयाब हो गये तो फिर उनसे निजात पाना काफी मुश्किल साबित होगा।

माओवादी शुरू से ही भारत विरोधी रहे हैं। अपने आन्दोलन के शुरूआती दिनों में माओवादियों ने जो चालीस मांगे रखी थी उनमें भारत के साथ करीबी रिश्ते खत्म करना भी था। हालांकि इनके प्रमुख नेता डा० बाबूराम भट्टाराई ने मार्क्सवाद और लेनिनवाद का पाठ सम्भवतः भारत के प्रतिष्ठित जवाहरलाल विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान ही सीखा हो। इसके बावजूद उनकी प्रमुख राजनीतिक मांगों में नेपाल में हिन्दी भाषा पर प्रतिबन्ध लगाना नेपाल में रह रहे विदेशियों (जिसमें भारतीय प्रमुख है) को नेपाल से बाहर निकालना और 1950 में दिल्ली और काठमाडूं के बीच हुए मित्रता संधि को रद्द करना प्रमुख रहे है, वे भारत को ऐसे देश के रूप में देखते हैं जो नेपाल पर कब्जा करना चाहता है, जबकि इस संदेह का उनके पास कोई ठोस आधार नही है। ऐसे में नेपाल में माओवादियों का बढ़ता प्रभाव मजबूत भारत-नेपाल सम्बन्धों के लिए समस्या उत्पन्न करेगा। नेपाल में माओवादियों. के विस्तार से भारत के कई राज्यों में भी इनकी गतिविधियाँ बढ़ने का अंदेशा है। भारत के आन्ध्रप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश आदि कई राज्यों के अनेक इलाकों में पीपुल्स बार ग्रुप (पी०डब्लु०जी०) और माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर ने अपनी गतिविधियाँ तेज कर दी हैं।[6]

भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तराखण्ड से लगी 275 किमी0 क्षेत्र में दोनों देशों के सर्वे दलों ने नो मैन्सलैंड के लिए 256 किमी० सीमा का सर्वे भी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दोनों देशों के उत्तराखण्ड से सटी सीमा के उच्चाधिकारियों की बैठक में सर्वे की 10 जुलाई 2003 को समीक्षा की गई जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में आई०एस०आई० और माओवादियों के अलावा असामाजिक तत्वों की सक्रियता की सूचनाओं को सही मानते हुए संदिग्ध गतिविधियों की सूचनाओं का आदान-प्रदान करने का निर्णय लिया गया, साथ ही सीमा पर सर्वे कर नो मैन्सलैंड घोषित करने की तैयारी भी शुरू की गयी।[7] नेपाल सीमा से माओवादियों की घुसपैठ रोकने के बावत सेना, आई०टी०बी०पी०, सेना पुलिस तथा एस०एस०बी० के साथ साझा रूप से कार्य किया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों में आबादी के बढ़ते ग्राफ के पीछे प्रदेश में बढ़ते रोजगार के अवसर ही मुख्य वजह समझी जा सकती है। उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्य सचिव आर०एस०टोलिया के अनुसार 28

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 07, July 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

अगस्त 2004 को पिथौरागढ़ के झूलाघाट कस्बे पर नेपाल से हुई गोलाबारी के बाद से सीमावर्ती जिलों में भय का माहौल व्याप्त हो गया था। माओवादियों और नेपाली सेना के बीच मुठभेड़ के चलते कुछ गोलियों भारतीय सीमा में आकर घुसी जिससे एक बच्ची भी घायल हुई। इस स्थिति में 30 अगस्त को रूद्रपुर में करीब आधा दर्जन माओवादियों की गिरतारी ने मौजूदा हालात में उत्प्रेरक का ही काम किया है। नेपाली माओवादियों की भारतीय सीमा में प्रवेश की हर सम्भावना को समाप्त करने के लिए बार्डर पर सेना आई०टी०बी०पी० तथा एस०एस०बी० को राज्य की प्रत्येक स्थिति से वाकिफ करा दिया गया है।[8]

नेपाल में माओवादी जिस तेजी से अपने पाँव पसार रहे हैं उससे लगता है कि उत्तराखण्ड राज्य ही नहीं भारत के अन्य राज्यों को भी भविष्य में बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त देश के नौ राज्यों की दस करोड़ आबादी माओवादियों के रहमों करम पर है जबकि तीन राज्यों में ये अपनी उपस्थिति दर्ज भी करा चुके हैं। जो राज्य माओवादियों से प्रभावित हैं उन इलाकों की प्रशासनिक व्यवस्था चौपट हो गयी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह हाल है कि चुनाव भी सही ढ़ग से सम्पन्न नही हो पा रहे है। आन्ध्रप्रदेश, विहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में माओवादी सक्रिय हैं। दुश्मन के सफाए में विश्वास रखने वाली एम०सी०सी० ने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक अपना जाल फैला लिया है। माओवादी वारदातों से देश का दसवाँ हिस्सा अशांत क्षेत्र में बदल गया है। अन्य राज्यों में चल रहे आतंकवादी संगठनों के माओवादी गठजोड़ से भारतीय उद्यमियों को अपने उद्योग-धन्धों को समेटने की चेतावनी दे दी गयी है। माओवादियों ने अन्तराष्ट्रीय आकार लेकर दुनिया के कई देशों में भी अपनी जड़ें जमा ली हैं। भारत-नेपाल से सटे कई राज्यों में माओवाद की बढ़ती घटनाओं ने दोनों देशों का माहौल गरमा दिया है। नेपाल में चल रहे गृहयुद्ध के चलते वहाँ से भारत आने वाले लोगों के कारण भारत में बढ़ते जनसंख्या दबाव से नेपाल से सटे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। रोजगार संसाधनों पर बढ़ते दबाव व पुलिस की बढ़ती सक्रियता ने आम नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया है। सत्तर के दशक के अर्तिम वर्षों में पश्चिम बंगाल के छोटे से गाँव से शुरू हुए नक्सलवाड़ी आन्दोलन आज देश के करीब नौ से अधिक राज्यों में पैर पसार चुका है। माओवादी देश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को शोषणकारी मानते हैं और सोची समझी राजनीति के तहत देश के ग्रामीणों और निर्धन जनता को उसके विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष कर उखाड़ने के लिए उकसाते रहते हैं। माकपा (माले) की स्थापना से लेकर अब तक दर्जनों बार इन संगठनों में टूट-फूट हुई है, पर बहुत से संगठन अब एकता की राह पर हैं। पीपुल्स बार ग्रुप ने तो मध्य भारत के एक बड़े क्षेत्र दंडकारण्य को गुरिल्ला जोन घोषित करते हुए उसे अपना आधार क्षेत्र बनाना चाहता है। एम०सी०सी० का प्रभाव ज्यादातर विहार व झारखण्ड राज्य में है। भारत की सीमाओं से लगे करीब तीन देशों में माओवादी संगठन सक्रिय हैं। नेपाल में हो रही माओवादी हिंसा तो देश की सीमा से सटे इलाकों में समस्या खड़ी करने लगी है।"[9]

भारत-नेपाल के लिए सिर दर्द बन चुके माओवादियों के तार अब पश्चिमी उत्तरप्रदेश से भी जुड़ गये हैं। वे अवैध हथियारों की मंडी कहे जाने वाला सहारनपुर क्षेत्र माओवादियों को भी अवैध असहले सप्लाई कर रहा है। हाल ही के दिनों में नेपाल में पकडे गये एक माओवादी से गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि देहरादून और सहारनपुर से संगठन ने अवैध हथियार खरीदे थे। केन्द्रीय खुफिया एजेन्सियों से यह सूचना मिलने के बाद प्रदेश में खुफिया तंत्र को सतर्क किया गया। इनकी गतिविधियों

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 07, July 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

उत्तराखण्ड के अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में होने की चर्चा तो काफी पहले से ही है। परन्तु अब माओवादियों की सक्रियता उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून और उससे सटे सहारनपुर जिलें में भी होने की जानकारी केन्द्र सरकार को मिली है।[10] पिछले वर्ष के अन्त तक नेपाल के माओवादी उग्रवादियों की उत्तराखण्ड में शरण लेने की खबर से उत्तराखण्ड सरकार पसोपेश की स्थिति में आ गयी थी। सरकार इनके खिलाफ क्या कार्यवाही करे और उस कार्यवाही का स्वरूप क्या हो, इसको लेकर सरकारी महकमों में असमंजस की स्थिति बरकरार है जिसे सरकार यह कहकर प्रदर्शित नही होने देत्ती कि उत्तराखण्ड में माओवादियों से कोई खतरा है। दरअसल सरकार के पास इन उग्रवादियों के राज्य में मौजूदगी और यहाँ उनकी तरफ से भारत-विरोधी गतिविधियाँ संचालित करने के बारे में कोई पक्की खबर नहीं है इसके चलते सरकार उनके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही शुरू नहीं कर पा रही है।

खुफिया महकमों से छन कर आने वाली खबरों के अनुसार राज्य की सीमाओं में नेपाल से माओवादी उग्रवादी और उनके राजनीतिक नेतृत्व से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता आगे आते रहते हैं। इन उग्रवादियों की पिछले एक साल में उत्तराखण्ड में शरण लेने की रफ्तार काफी बढ़ी है। वर्तमान समय नेपाल सरकार ने जिस तरह माओवादियों के खिलाफ अपनी सैनिक कार्यवाही तेज की है, उससे उन्हें वहाँ भारी तकलीफ होने लगी है। हालिया खूनी संघर्षो में उन्हें जन-धन की काफी हानि उठानी पड़ी है। खुफिया एजेन्सियों का अनुमान है कि माओवादी नेताओं के बच्चे भी देहरादून की - ख्यातिप्राप्त स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं जिनमें अधिकांश अंग्रेजी माध्यम के ही स्कूल हैं। इन सभी कारणों से उनका उत्तराखण्ड की सरहद में घुस आने की सम्भावनाएँ शुरू से ही काफी आँकी जा रही थी। सूत्रों के अनुसार ये माओवादी भले यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं पर वे किसी न किसी माध्यम से नेपाल पर नजर रखे रहते हैं। सितम्बर-अक्टूबर 2004 में एक माओवादी सपत्नीक गुजर-बसर करने के कुछ हफ्ते बाद वापस नेपाल लौटने की पुष्टि भी हो चुकी है तथा इसी वर्ष 2005 में देहरादून से एक माओवादी को पकड़ कर नेपाल पुलिस को सौंपा जा चुका है। भले ही सरकार न खुले आम स्वीकार नही करती कि नेपाल के माओवादी उत्तंराचल में शरण लिए हुए हैं, पर इसकी आशंका से इनकार भी नही करती।"

नेपाल में सक्रिय माओवादियों ने भारत के हुक्मरानों को चेतावनी दी है कि वे नेपाल को सैन्य मदद देने के अपने मंसूबे से बाज आये, वरना उनका चुनचुन कर सफाया किया जायेगा और इस काम को अंजाम देंगे मानव बम। इस तरह के पोस्टर कुमाऊँ में देखे जाने के बाद पुलिस और खुफिया तंत्र की नींद उड़ गयी जिससे लोगों में खौफ फैल गया। सितम्बर 2004 को भारतीय सीमा में भारत-नेपाल पुल पर में की नेपाली भाषा में लिखे दो पोस्टर चिपके मिले। जिन पोस्टर भास्तीय शासन को चेतावनी देते हुए कहा गया था कि हम 21वीं शताब्दी में भी सामंती व्यवस्था और निरंकुश राजतंत्र को सहन नहीं करेंगे। भारतीय शासक नेपाल को सैन्य मदद देने का ख्याल छोड़ दे, अन्यथा मानव बम भारत भेजकर उनका सफाया कर दिया जायेगा। पोस्टर में वैतड़ी सीमा में की गई नाकेबन्दी को न्यायपूर्ण बताते हुए यह उम्मीद जताई गई कि भारतीय शासक मानव बम भेजने जैसी स्थिति नही आने देंगे। पोस्टर में माओवादियों के तत्कालीन एरिया सचिव गजाधर भट्ट, एरिया इंचार्ज ज्योति भट्ट, जगन्नाथ भट्ट के हस्ताक्षर थे। यह इसी वर्ष भारत दौरे पर आये नेपाली प्रधानमंत्री भोर बहादुर देउवा को आतंकवाद से लड़ने, सुरक्षाबलों और नेपाली पुलिस को मजबूत करने के लिए सहयोग देने के आश्वासन पर माओवादियों का एतराज जताने का तरीका था।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 07, July 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

गौरतलब है कि पोस्टरों में भारत-नेपाल मैत्री सम्बन्धों को हवाला देते हुए कहा गया था कि नेपाल में वह विदशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे।[12]" इन पोस्टरों की छपाई उत्तराखण्ड में ही की गई थी यह बात तब सामने आई जब एस०एस०बी० की गिरफ्त में आये माओवादी एरिया कमाण्डर खेमराज भट्ट ने टनकपुर में बताया कि पिथौरागढ़ में माओवादी समर्थकों ने जो पोस्टर पिछले दिनों चिपकाए गये, उनकी छपाई पिथौरागढ़ में ही हुई। अतः समझा जा सकता है कि चंद कागजी नोटो के लिए कुछ स्वार्थी तत्व अपना जमीर तक भी बेच सकते है। आज उनके द्वारा माओवादियों को पराश्रय एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो कल आई०एस०आई० द्वारा बड़ी रकम मिलने पर क्या वे मुकर जायेगे, जो एक सोचनीय पहलू है और यह उतरांचल की गौरवशली परम्परा पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देती है। वर्तमान समय में सीमा पार नेपाल के मदरसों व मुस्लिम संगठनों को माओवादी और पाक की खुफिया एजेन्सी आई०एस०आई मदद दे रही है। इसके चलते माओवादियों की देख-रेख में नेपाल में भारत विरोधी प्रचार तेजी पकड़ रहा है। इस प्रचार को तीखा करने में नेपाल के माओवादी देश के नक्सली संगठनों के साथ मेलजोल बढ़ाने में जुट गये है। नेपाल में हो रही इन गतिविधियों की जानकारी सशस्त्र सीमा बल (एस०एस०बी०) के पूर्व महानिदेशक हिमांशु कुमार ने बताया कि नेपाल में माओवादियों की गतिविधियां चिन्ताजनक है, क्योंकि इन लोगों ने नेपाल के एक तिहाई जिलों में अपना प्रभुत्व जमा लिया है। और अब ये माओवादी नेपाल में भारत विरोधी प्रचार को तेज करने में जुटे है। जिसके चलते उन्होनें महाराजगंज, बलरामपुर सिद्धार्थनगर, बहराइच व पिथौरागढ़ के नजदीक के नेपाली क्षेत्र में खाई खोद दी है लाकि क्षेत्रीय जनता पर भारत से मदद मिलने की भावना खत्म की जा सके।"[14]

सर्वविदित है कि कुमाऊँ की शांत वादियों में वर्ष 2004 से पलगा का आतंक छाया रहा। एक समय उसके वर्दीधारी सदस्य प्रशासन के लिए गले की हड्डी बन गये थे। एम०सी०सी०आई झारखण्ड की इस उत्तराखण्ड शाखा ने यहाँ अपनी जबरदस्त पैठ बनाकर भोले-भोले लोगों को फौज में भर्ती होने का लालच देकर हथियारों का प्रशिक्षण देने लगे, जिनमें गरीब मजदूर व किसान वर्ग के लोग ही शामिल थे। विवेक सक्सेना की रिर्पोट के अनुसार कुमाँऊ मण्डल में इसके 25 सक्रिय सदस्य - है। जिन्होनें विगत वर्ष 22 अप्रैल 2004 की उत्तराखण्ड शाखा का प्रथम स्थापना दिवस मनाया, जिससे पूरा प्रशासनिक महकमा व खुफिया तंत्र सकते में आ गया था। । नक्सली ग्रुप की इस क्षेत्र में पहली बार नही अपितु इससे पूर्व 1987 में भी इस ग्रुप के कुछ प्रशिक्षितों ने हिमालयन कार रैली पर पेट्रोल बम फेंककर राज्य आन्दोलन को हिंसक रुप देने का प्रयास किया था। इतना ही नही पलगा ग्रुप ने एक बार शांत पहाड़ की वादियों में अशांति फैलाने के लिए दिल्ली दूर, बीजिंग पास के नारे अनेक सरकारी भवनों पर लिख दिये थे। इस बीच राज्य आन्दोलन के साथ-साथ राम जन्म भूमि ई आन्दोलन भड़क जाने से पलगा के प्रमुख नक्सली छत्तीसगढ़ और देश के अन्य भागों को चले गये।"[15]

अतः स्पष्ट है कि अगर ये संगठन चीन का समर्थन करते है, तो माओवादियों से न भी इनकी सहानुभूति स्वाभाविक है। उत्तराखण्ड में माओवादियों के सम्भावित ठिकाने निम्नवत् है:

1- पिथौरागढ़ पूरी धारचूला तहसील।

2- चंपावत- टनकपुर और सितारगंज तहसील।

3- नैनीताल बनवसा, खटीमा तहसील तथा चोरगलियाँ।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 07, July 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

4 चमोली जोशीमठ, चमोली, गोपेश्वर, पीपलकोटी, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, थराली।

5 - उत्तराकाशी- विकासखण्ड मोरी, नौगांव, पुरोला, भटवाड़ी।

6 देहरादून कालसी, त्यूनी, चकराता, विकासनगर, डाकपत्थर।

इसी सन्दर्भ में एम०सी०सी०आई० (झारखण्ड) के दिशा निर्देशन एवं उत्तराखण्ड शाखा के रूप में लगभग 2 वर्ष से सक्रिय रहे ये संगठन पुनः पूरे राज्य में गरीब, मजदूर व बेरोजगारों को अपना लक्ष्य बनाकर इन्हें अपने पक्ष में करने का काम कर रहे है। इस संगठन से जुड़े लोग सरकार विरोधी बातें कर इन भोले-भाले लोगों को अपने हैं साथ जोड़कर अपना काडर बढ़ाने की मुहिम चला रहे है। इतना ही नहीं सिर्फ बंदूक के जोर पर समान अधिकार मिलने की बात कहकर इस संगठन से जुड़े करीब 12 लोग इस समय कुमाऊँ मण्डल के जंगलो में रहने वाले निर्धन किसान, मजदूरो को 12 बोर की 6 तथा 315 बोर की 5 बंदूकें तीन देशी तमंचो से ग्रामीणो को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दे रहें है। इसके अलावा वे चित्रों के माध्यम से ग्रामीणों को अन्य स्वचालित हथियारों की जानकारी भी उपलब्ध करा रहे है। यही नहीं राज्य के सुदूर बीहड़ जंगलो में ये गाँव के युवक-युवतियों को विशेष प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम फौजी प्रशिक्षण भी दे रहे है। एक खास बात यह है कि इस 12 लोगों के गिरोह में 1 व्यक्ति मद्रास का है जो फौजी ट्रेनिंग दे रहा है तथा शेष सदस्य पर्वतीय मूल के है, जिसमें दो युवतियाँ भी शामिल है। इस बात का खुलासा पुलिस द्वारा जंगलो में सघन कार्बिंग करने के बाद हो पाया गया है। आशाएँ जतायी जा रही है कि ये संगठन नेपाली माओवादियों से ज्यादा खतरनाक है। इसको अगर शीघ्र नेस्तनाबूत नहीं किय गया तो पूरे राज्य के लिए यह भयानक समस्या विकराल रुप धारण कर लेगी।"[16]

नेपाल की आन्तरिक स्थिति उत्तराखण्ड को ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र को प्रभावित करती है। जहाँ तक इसका प्रभाव देखा जाए तो प्रत्यक्ष रुप से यह उत्तराखण्ड की आर्थिकी को प्रभावित करता है तथा जहाँ तक माओवादियों का प्रश्न है तो उनसे भारतीय पक्ष को सिर्फ चिन्ता का विषय यह है कि वे भारत विरोधी दुश्प्रचार नेपाल में कर देता है और भारत से तटस्थ रहने की अपनी बात पर अड़े रहते है, हालाँकि लोग माओ विचाराधारा को लेकर तथा चीन का सहारा लेकर तूल देते रहते है, परन्तु शायद ये लोग नही जाने कि भारत के बिना इनके देश का अस्तित्व भी लडखड़ा सकता हैं तथा जहाँ तक मै समझता हूँ कि विश्व में शायद ही कोई ऐसा राष्ट्र होगा जो निहित स्वार्थो से परे होकर किसी राष्ट्र को सम्पन करने या सोचने की दिली इच्छा रखता हो तो क्या शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों की श्रेणी में आने वाला चीन एक गरीब राष्ट्र नेपाल का इतना बड़ा हिमायती या हितैषी हो सकता है और वो भी तब जब चीन अपनी सहानुभूति का परचम तिब्बत में लहरा चुका हो। अतः नेपाल की तत्कालीन परिस्थितियों में जब वहाँ समाज का युवा वर्ग राजशाही से क्षुब्ध होकर माओवादियों का साथ दे रहे हैं तो चीन की किसी बात का अधिसंख्यक जनता पर प्रभाव पड़ेगा। और अगर ऐसा ही हुई हो गया तो नेपाल पूर्णतः चीन पर आश्रित हो जाएगा और चीन के ही इशारों पर चलता रहेगा परिणामस्वरुप भारत की लगभग शांत पड़ी उत्तरी सीमा को कश्मीर जैसे हाल का सामना करना पड़ सकता है।

अन्त में मैं कहना चाहूँगा कि चाहे अभी तक माओवादी या नेपालजन्य स्थिति से उत्तराखण्ड को कोई आघात न पहुँचा हो और यह सम्भव भी न हो परन्तु एक बार तो अशांति की हवा प्रारम्भ हो ही गयी थी

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 07, July 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

तथा जिसका आगे भी फैलने का अंदेशा किया जा सकता है। क्योंकि नेपाल में परिस्थितियाँ अभी अनुकूल नहीं है, अपितु प्रतिकूल ही छोड़ दी जाती है तो माओवादियों के पास शरण लेने के लिए उत्तराखण्ड ही प्रमुख विकल्प होता है जो नेपाली सरकार के लिए चिन्ता का विषय बन जाता है और साथ ही उत्तराखण्ड सरकार कहती है कि मित्र राष्ट्र के विरुद्ध प्रदेश से किसी भी प्रकार की गतिविधि को चलाने नहीं दिया जाएगा। जिससे कुछ स्थितियों में जब चाहे अफवाहे ही फैलायी जा रही है। पूरे प्रशासनिक मकहमे में अस्त व्यस्तता आ जाती है. जिसका सीधा प्रभाव विकास सम्बन्धी गतिविधियों पर पड़ता है।

## संदर्भ सूची

1- सुमित जखमोला, ग्लोबल न्यूज- "नेपाल में फिर शाही शासन", मार्च 2005 पृ०स०-06।
2- लल्लन जी सिंह, पर्वत पीयूष लेख "उत्तराचंल सीमा पर माओवादी खतरा" 06 नवम्बर 2003, पृ०सं० 22।
3- बी०एस० तोपाल, दैनिक जागरण "कब होगा नेपालियों का सत्यापन 05 सितम्बर 2004 |
4- विकास घुलिया, दैनिक जागरण 05 सितम्बर 2004 ।
5- विजय कुमार झा, "भारत के लिए खतरा", जागरण 17 मार्च 2002।
6- अमर उजाला 10 जुलाई 2003।
7- अमर उजाला 02 सितम्बर 2004
8- अरविन्द शेखर, अमर उजाला, 12 सितम्बर 2004 |
9- अमर उजाला, 13 सितम्बर 2004 |
10-अमर उजाला, 03 सितम्बर 2004 |
11-अमर उजाला, 15 सितम्बर 2004 |
12-रक्षार्थ नवभारत टाइम्स, पृ०स० 28 दिसम्बर 2007।
13-दैनिक जागरण 09 सितम्बर 20041
14-दैनिक जागरण 05 सितम्बर 2004 1
15-दैनिक जागरण 05 सितम्बर 2004 1
16-दैनिक जागरण 05 सितम्बर 2004 1